किस्त आपूर्ति (पी.) लिमिटेड और एक अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

[बी. पी. सिन्हा, सी. जे., एस. के. दास, ए. के. सरकार, एन. राजगोपाला अयंगर और जे. आर. मुधोलकर, जे. जे.]

2 मई, 1961

बिक्री कर- किराया-खरीद समझौता- क्या ऐसे समझौते पर लेनदेन पर कर लगाया जा सकता है- बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941, दिल्ली राज्य तक विस्तारित, धारा 2(जी)।

बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की धारा 2(जी), जैसा कि दिल्ली राज्य तक विस्तारित है, निम्नानुसार प्रावधान किया गया है-

"'बिक्री' का अर्थ है नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण, जिसमें अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण शामिल है, लेकिन इसमें बंधक, दृष्टिबंधक, शुल्क या गिरवी शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण 1.... किराया-खरीद या भुगतान की अन्य किस्त प्रणाली पर माल का हस्तांतरण, इस बात के बावजूद कि विक्रेता कीमत के

भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में किसी भी माल का शीर्षक रखता है, बिक्री माना जाएगा।"

याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा किए गए किराया-खरीद समझौते में यह प्रावधान था कि सभी मासिक किस्तों का भुगतान करने के बाद, "किराया समाप्त हो जाएगा और वाहन, किराएदार के विकल्प पर, उसकी पूर्ण संपत्ति बन जाएगा; लेकिन जब तक उपरोक्त जैसे भुगतान किए गए हैं, वाहन मालिकों की संपत्ति बना रहेगा। किराएदार के पास इस समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय वाहन खरीदने का विकल्प होगा, जिसमें यहां पहले उल्लिखित सभी किराये की शेष राशि और लेनदेन से संबंधित मालिकों द्वारा किए गए किसी भी अन्य खर्च का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। निर्धारण के लिए प्रश्न यह था कि क्या समझौता अधिनियम की धारा 2(जी) के स्पष्टीकरण 1 के अर्थ के तहत केवल किराये पर लेने का लेनदेन था या किराया-खरीद में से एक था।

अभिनिर्धारित, अधिनियम की धारा 2(जी) के स्पष्टीकरण 1 की भाषा इतनी व्यापक थी कि इसमें स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना केवल माल का हस्तांतरण शामिल किया जा सकता था, यदि ऐसा स्थानांतरण किराया-खरीद समझौते या भुगतान की किसी अन्य किस्त प्रणाली के दौरान हुआ हो।

चूंकि अधिनियम में 'किराया-खरीद' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था, इसलिए इसे इसके सामान्य सामान्य कानून अर्थ में समझा जाना चाहिए, यानी, यह बिक्री के तत्व के साथ जमानत के अनुबंध की प्रकृति का हिस्सा है।

ली बनाम बटलर, [1893] क्यू.बी. 318 और हेल्बी बनाम मैथ्यूज, [1895] ए.सी. 471, संदर्भित।

अधिनियम की धारा 2(जी) के स्पष्टीकरण 1 में गैर-अप्रत्याशित खंड उक्त स्पष्टीकरण के मुख्य खंड को नियंत्रित नहीं करता था और इसका एकमात्र उद्देश्य उसमें निहित कानून के स्पष्ट कथन पर जोर देना था। चूंकि मौजूदा मामले में समझौते में न केवल जमानत का अनुबंध शामिल था, बल्कि बिक्री का एक तत्व भी शामिल था, लेन-देन उचित रूप से बिक्री कर के अधीन किया गया था।

इस तर्क में कोई बल नहीं हो सकता है कि अधिनियम जहां तक बिक्री की अवधारणा को उस चीज़ तक विस्तारित करने की मांग करता है जो कानून में वास्तविक बिक्री नहीं थी, असंवैधानिक था।

मिथन लाल बनाम दिल्ली राज्य, [1959] एससीआर 445, संदर्भित

न ही इस तर्क में कोई दम था कि अधिनियम में 'बिक्री' शब्द की विस्तारित परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। यह

सुस्थापित है कि कराधान के मामलों में पूर्व न्यायिकता का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

सोसाइटी ऑफ मेडिकल ओफिसर्स ऑफ हेल्थ बनाम होप (मूल्यांकन अधिकारी), [1960] ए.सी. 551 और ब्रोकन हिल प्रोप्राइटरी कंपनी लिमिटेड बनाम म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ ब्रोकन हिल, [1925] ए.सी. 94, संदर्भित।

इंस्टालमेंट सप्लाई लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम दिल्ली राज्य, ए.आई.आर. 1956 पंजाब 177, पर विचार किया गया।

मूल क्षेत्राधिकार: याचिका संख्या 146/1958।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिका।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वेद व्यास, एस.के. कपूर और गणपत राय।

प्रतिवादियों की ओर से सीके दफ्तरी, भारत के सॉलिसिटर-जनरल, आर. गोपालकृष्णन और डी. गुप्ता।

1961, 2 मई।

न्यायालय का निर्णय सिन्हा, सीजे द्वारा सुनाया गया।

याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में एक याचिका या आदेश परमादेश और/या निषेध और/या अन्य उपयुक्त रिट के रूप में, याचिकाकर्ताओं द्वारा किराया-खरीद समझौतों के रूप में दर्शाए गए लेनदेन पर किसी भी बिक्री कर को न लगाने, चार्ज करने या एकत्र न करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश या निर्देश देने के लिए दाखिल की है, जिसका एक विशिष्ट उदाहरण याचिका के अनुबंध 'ए' में शामिल है, जिसकी आगे विस्तार से जांच की जाएगी।

पहला याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जनपथ, नई दिल्ली में है। दूसरा याचिकाकर्ता उस कंपनी का प्रबंध निदेशक और शेयरधारक है और इस आवेदन के परिणाम से सीधे तौर पर संबन्धित है, क्योंकि दावा किया गया है कि उसके अधिकार और संपत्ति सीधे तौर पर इसमे शामिल हैं। कंपनी दिल्ली में नई और सेकेंड-हैंड मोटर कारों और अन्य प्रकार के मोटर वाहनों की खरीद के वित्तपोषण का कारोबार कर रही है। उपरोक्तानुसार किसी खरीद के वित्तपोषण के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणाली इस प्रकार है। मोटर वाहन खरीदने का इच्छुक व्यक्ति मालिक के साथ सौदा तय करता है और याचिकाकर्ता कंपनी याचिका के अनुबंध 'ए' के रूप में चिह्नित समझौते की मुद्रित प्रति में दिखाई देने वाले नियमों और शर्तों पर आवश्यक वित्त प्रदान करेगी। उस समझौते के अनुसार, कंपनी वाहन का पट्टा देने के लिए प्रीमियम के रूप में 'किराएदार' से प्रारंभिक जमा राशि

लेती है, जो जमा राशि कंपनी की पूर्ण संपत्ति बन जाती है; ऊपर बताया गया प्रीमियम एक बड़ी राशि है, जो आमतौर पर नए वाहनों के संबंध में कीमत का 25% होती है। 'किराएदार' किस्तों का भुगतान करने का वचन देता है और जब सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाता है, तो विकल्प के लिए प्रतिफल के रूप में, कंपनी को एक रुपये का भुगतान करने पर, वाहन 'किराएदार' की संपत्ति बन जाता है; जब तक सभी निर्धारित किश्तों का भुगतान नहीं कर दिया जाता और उपरोक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक वाहन मालिक के रूप में कंपनी की संपत्ति बनी रहेगी। 'किराएदार' को वाहन का कब्ज़ा दे दिया जाता है और वह क्षति या विनाश या हानि के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार रहता है। 'किराएदार' को प्रति माह सभी अतिदेय राशियों पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। जब तक 'किराएदार' द्वारा खरीद के विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक वह कुछ शर्तों पर वाहन वापस करने और किराये के समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार, समझौते के तहत, 'किराएदार' वाहन का उपयोग करता है, जो उसे कंपनी की संपत्ति के रूप में सौंपा गया है, और यह 'किराएदार' के लिए उपर्युक्त के अनुसार वाहन का खरीदार बनने के लिए खुला है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि कंपनी द्वारा प्राप्त किराया, बेची गई वस्तुओं की कीमत का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार बिक्री मूल्य के रूप में कर लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम,

1941 (बंगाल अधिनियम VI/1941) दिल्ली राज्य तक विस्तारित किया गया था, जो अब दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश है। उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, बिक्री कर अधिकारियों ने उपरोक्त प्रकृति के सभी लेनदेन पर इस आधार पर बिक्री कर की मांग करना और लेवी लगाना शुरू कर दिया कि कंपनी को किराए पर लेने वालों द्वारा भुगतान की गई किश्तें बिक्री-मूल्य थीं और इसलिए, बिक्री कर के लिए उत्तरदायी है। कंपनी ने बिक्री कर अधिकारियों के ऐसे किसी भी कर को लगाने के अधिकार को इस आधार पर चुनौती दी कि यह कानून विधायिका की क्षमता से परे है। अंततः, कंपनी ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत पंजाब उच्च न्यायालय (दिल्ली में सर्किट बेंच) का दरवाजा खटखटाया। रिट याचिका में, जिसे सिविल रिट आवेदन संख्या 289-डी/1954 के रूप में पंजीकृत किया गया था, कंपनी ने प्रतिवादी को बंगाल अधिनियम, दिल्ली तक विस्तारित प्रावधानों के तहत किसी भी बिक्री कर को वसूलने या लगाने से रोकने के लिए निषेध और/या परमादेश की प्रकृति में एक रिट की प्रार्थना की। 1953-54 में बिक्री कर अधिकारियों द्वारा पारित कुछ आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी (उत्प्रेषण) रिट के लिए भी प्रार्थना की गई थी। उक्त आवेदन पर एक डिवीजन बेंच ने सुनवाई की, जिसने याचिका को अनुमति प्रदान की और राज्य को बिक्री कर की वसूली के लिए अपने नोटिस को लागू करने से रोकने के लिए एक परमादेश जारी किया। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य

विधानमंडल के पास माल की बिक्री अधिनियम द्वारा जुड़े अर्थ से परे जाकर "माल की बिक्री" शब्द के अर्थ को बढ़ाने की शक्ति नहीं थी। पंजाब उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त फैसले के बाद, यह आगे आरोप लगाया गया है कि, दिल्ली में किराया-खरीद व्यवसाय करने वाली कंपनियों और बिक्री कर आयुक्त के बीच एक समझौता हुआ, जिन्होंने एक परिपत्र जारी किया, जो परिपत्र संख्या 10/1956 है, में विभाग के निम्नलिखित निर्णय शामिल हैं:

> "(i) जो कंपनियाँ विशेष रूप से किराया खरीद व्यवसाय में लगी हुई हैं, उन्हें डीलर नहीं माना जाएगा और उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।
>
> (ii) जो कंपनियाँ आंशिक रूप से किराया खरीद के व्यवसाय में लगी हुई हैं, वे पहले की तरह डीलर बनी रहेंगी और उनके किराया खरीद लेनदेन की पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में उचित जांच की जाएगी, और वे एक समय पर बिक्री कर के लिए उत्तरदायी होंगी।
>
> (iii) उपरोक्त (i) के परिणामस्वरूप, डीलरों द्वारा उपरोक्त कंपनियों को की गई वाहनों की बिक्री पर बाद वाले के हाथों बिक्री कर लगेगा।
>
> (iv) वाहनों और मशीनरी आदि के संबंध में, जिनके लिए बाजार से खरीद के समय कर का भुगतान किया गया है,

किराया खरीद कंपनियों द्वारा उन पर एकत्र किए गए किराया धन के संबंध में या पुनर्विक्रय के बाद उनकी पुनः बिक्री या पुनः काम पर रखने पर या किराएदार द्वारा खरीद के विकल्प के प्रयोग पर कोई बिक्री कर देय नहीं होगा।

(v) कंपनियों द्वारा किराया खरीद के उद्देश्य से निजी व्यक्तियों से खरीदे गए सेकेंड हैंड वाहनों के संबंध में, कंपनियां खरीद के समय या उसके बाद के लेनदेन के संबंध में किसी भी बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। कंपनियाँ अन्य गैर-पंजीकृत डीलरों की तरह होंगी, (i) के मद्देनजर किराया खरीद व्यवसाय के संबंध में उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाने के कारण।

(vi) मेसर्स किस्त आपूर्ति कंपनी लिमिटेड के मामले को छोड़कर, जिनका मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका है उसे दोबारा नहीं खोला जाएगा, जिसके लिए उच्च न्यायालय के निर्दिष्ट आदेश हैं।

(vii) अपने अद्यतन मूल्यांकन में, किराया खरीद कंपनियों को उस कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो उन्होंने डीलरों या गैर-पंजीकृत डीलरों से कर मुक्त

खरीदारी करके बचाया है। हालाँकि, मूल्यांकन पहले की तरह सामान्य तरीके से किया जाएगा।"

इसके बाद मिठन लाल बनाम दिल्ली राज्य के मामले में इस न्यायालय ने दिल्ली तक विस्तारित बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की जांच की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कानून वैध रूप से प्रख्यापित किया गया था। उस निर्णय के अनुसार, 'बिक्री' की परिभाषा को कानूनी रूप से बढ़ाया जा सकता है ताकि भवन निर्माण अनुबंधों के अनुसरण में सामग्री की आपूर्ति से जुड़े सामानों की बिक्री पर कर लगाने की अनुमति दी जा सके। इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप, बिक्री कर आयुक्त, दिल्ली द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि किराया-खरीद लेनदेन पर कर लगाने के संबंध में प्रावधान वैध था और सभी किराया-खरीद डीलर बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की धारा 4 और 7 के दायरे में आते हैं, जैसा कि दिल्ली तक विस्तारित है, बिक्री कर का भुगतान करने और अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कराने के लिए उत्तरदायी हैं; ऐसे सभी किराया-खरीद डीलर जो पहले बिक्री कर विभाग के साथ पंजीकृत थे, उन्हें अधिनियम के प्रयोजन के लिए पहली अप्रैल, 1958 से पंजीकृत माना जाएगा और सभी किराया-खरीद डीलर जिन्होंने अब तक खुद को पंजीकृत नहीं करवाया था, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित होने से बचने के लिए स्वयं को तुरंत पंजीकृत करवा लें। विभाग के उक्त परिपत्र

के अनुसरण में याचिकाकर्ता कंपनी को भी अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए कहा गया था। कंपनी ने बिक्री कर आयुक्त को अभ्यावेदन दिया कि कंपनी और अन्य ऐसी कंपनियां जो किराया-खरीद का काम करती हैं, वे बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन बिक्री कर आयुक्त ने कंपनी के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और निम्नलिखित जवाब दिया:

> "1. ऐसे लेन-देन पर बिक्री कर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। हालाँकि, यदि वाहन दिल्ली में व्यवसाय करने वाली कंपनी द्वारा उस राज्य के बिक्री कर के भुगतान पर दिल्ली के बाहर के डीलर से खरीदे जाते हैं और वाहन उसी राज्य में पार्टी को किराए पर खरीदा जाता है, तो न तो दिल्ली बिक्री कर और न ही इस तथ्य के बावजूद कि किराया-खरीद समझौता दिल्ली में दर्ज किया गया है, दिल्ली की फर्म पर केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाएगा।
>
> हालाँकि, यदि वाहन राज्य 'ए' में खरीदा गया है, लेकिन राज्य 'बी' में किसी पार्टी को किराये पर दिया गया है, तो उस राज्य में लागू नियमों के अनुसार राज्य में केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाएगा।

2. सेकेंडहैंड वाहनों के किराया-खरीद लेनदेन, जहां मालिक वाहनों के खिलाफ वित्त के लिए किराया खरीद कंपनी से संपर्क करता है, बिक्री कर लगाया जाएगा, क्योंकि किराया-खरीद समझौते के अनुसार वाहन की संपत्ति किराया खरीद कंपनी में निहित है और यह संपत्ति किराया-खरीद लेनदेन के आधार पर तथाकथित मालिक को हस्तांतरित की जानी है।

दिल्ली के बाहर खरीदे गए सेकेंडहैंड वाहन और दिल्ली के बाहर की पार्टियों को किराए पर खरीदे गए या दिल्ली के बाहर किए गए किराया-खरीद लेनदेन, जिसमें मालिक वित्त के लिए किराया-खरीद कंपनी से संपर्क करता है, ऊपर 1 में दिए गए स्पष्टीकरण द्वारा शासित होंगे।

3. स्थानीय पंजीकृत डीलरों से किराया खरीद कंपनियों द्वारा खरीदे गए वाहनों के मामले में, उन्हें किसी भी बिक्री कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सभी किराया खरीद कंपनियां पंजीकृत होंगी और ऐसे वाहनों की कर मुक्त खरीद करने की हकदार होंगी। इसलिए, खेद है कि इस संबंध में किए गए अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।

4. किराया-खरीद कंपनी द्वारा किरायेदार से ली गई कुल राशि पर बिक्री कर देय होगा और तथाकथित आकस्मिक शुल्कों पर बिक्री कर माफ करना संभव नहीं है।

5. यह खेदजनक है कि किराया-खरीद कंपनी की देनदारी की तारीख को बदलना संभव नहीं है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में 1 अप्रैल, 1958 से तय कर दी गई है। यह सच है कि प्रेस नोट जून के महीने में जारी किया गया था और इसलिए किराया-खरीद कंपनियां बिक्री कर के भुगतान पर वाहनों की खरीद कर रही हैं। किराया-खरीद कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए बिक्री कर की वापसी के लिए डीलरों से संपर्क करें।

हालाँकि, यदि किसी किराया खरीद कंपनी के लिए उनके द्वारा भुगतान किए गए बिक्री कर का रिफंड प्राप्त करना संभव नहीं है, तो भुगतान की गई राशि को किराया खरीद लेनदेन पर उनकी देयता के लिए समायोजित किया जा सकता है।"

विभाग का उत्तर प्राप्त होने पर, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है, याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस आधार पर इस

न्यायालय की ओर रुख किया कि "प्रतिवादियों की धमकी भरी कार्रवाई अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि याचिकाकर्ता कंपनी लेनदेन पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।"

याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क दिये हैं: (1) कि जिन लेनदेन के संबंध में याचिकाकर्ताओं पर कर लगाने की मांग की गई है, वे बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम की धारा 2(जी) के स्पष्टीकरण में शामिल नहीं हैं, जैसा कि दिल्ली तक विस्तारित है; (2) वैकल्पिक रूप से, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह माना जाता है कि स्पष्टीकरण पूर्वोक्त प्रकृति के लेनदेन को कवर करता है, तो 'बिक्री' की अवधारणा का विस्तार करने वाला स्पष्टीकरण असंवैधानिक है; (3) किसी भी मामले में यह असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जहां तक दिल्ली राज्य को शत्रुतापूर्ण भेदभाव के लिए चुना गया है; (4) कि किस्त आपूर्ति लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम दिल्ली राज्य (ए.आई.आर. 1956 पंजाब 177) में पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय उस निर्णय के पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक है; (5) यदि यह माना जाता है कि ऊपर उल्लिखित पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले को मिठन लाल के मामले ((1959) एस.सी.आर. 445) में इस न्यायालय के फैसले से हटा दिया गया है, तो उस फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है; और (6) अंत में, कि विभाग और "किराया-खरीद" में व्यवसाय करने वाली कंपनियों के बीच समझौता

उपरोक्त मिठन लाल के मामले ((1959) एस.सी.आर. 445) में इस न्यायालय के निर्णय तक बाध्यकारी है। हम इन तर्कों की जांच उसी क्रम में करेंगे जिसमें उन्हें कहा गया है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है: लेन-देन की वास्तविक प्रकृति और स्वरूप क्या है जो वर्तमान विवाद का विषय है? क्या याचिका के अनुबंध 'ए' में उल्लिखित समझौते की शर्तें, जैसा कि ऊपर वर्णित है, केवल किराये का समझौता है, जैसा कि प्रश्नगत क़ानून में निहित 'बिक्री' की परिभाषा के स्पष्टीकरण (1) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया है, या क्या वे किराया-खरीद का अनुबंध बनाते हैं? जैसा कि प्रतिवादियों की ओर से तर्क दिया गया है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'बिक्री' की अवधारणा, जैसा कि परिभाषा के निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट होती है, स्पष्टीकरण (एल) के साथ, बल्कि विस्तारित है। अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'बिक्री' शब्द की परिभाषा में, शब्द इस प्रकार हैं: -

> "'बिक्री' का अर्थ है नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले माल के स्वामित्व का कोई हस्तांतरण, जिसमें अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है, लेकिन इसमें बंधक, दृष्टिबंधक, शुल्क या गिरवी रखना शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण ।- किराया-खरीद या भुगतान की अन्य किश्त प्रणाली पर माल का हस्तांतरण, इस बात के बावजूद कि विक्रेता कीमत के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में किसी भी सामान का स्वामित्व बरकरार रखता है, बिक्री माना जाएगा।"

परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें न केवल वह शामिल है जिसे माल की बिक्री अधिनियम के तहत बिक्री के रूप में वर्णित किया जा सकता है, बल्कि लेनदेन भी शामिल है, जो सख्ती से बिक्री नहीं है,

'बिक्री के अनुबंध' भी नहीं, बल्कि इसमें केवल बिक्री का एक तत्व शामिल है, यानी खरीदने का विकल्प, और यही कारण है कि स्पष्टीकरण "बिक्री के रूप में समझा जाए" शब्दों के साथ समाप्त होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि एक कानूनी कल्पना है इसे 'बिक्री' की अवधारणा में पेश किया गया जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। स्पष्टीकरण में इसके दायरे में केवल माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना माल के हस्तांतरण को शामिल किया गया है, यदि यह "किराया-खरीद" या भुगतान की अन्य किस्त प्रणाली की प्रकृति के समझौते के दौरान है। सामान्य कानून के तहत किराये का अनुबंध, जमानत के अनुबंध के प्रकारों में से एक है और पिछले 60-70 वर्षों के दौरान, आधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के परिणामस्वरूप इसमें कई सुधार हुए हैं। अधिनियम

में 'किराया-खरीद' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, हमें अभिव्यक्ति को इसके सामान्य कानून अर्थ में समझना होगा, जिसे पृष्ठ 913-914 पर अर्ल जोविट द्वारा अंग्रेजी कानून के शब्दकोश के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार है:

> "किराया-खरीद एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत माल का मालिक उन्हें किराए पर लेने वाले द्वारा समय-समय पर भुगतान के लिए एक समझौते पर किराए पर देता है कि जब एक निश्चित संख्या में भुगतान पूरा हो जाएगा, तो माल का स्वामित्व किराए पर लेने वाले के पास चला जाएगा, लेकिन ऐसा किराये पर लेने वाला किसी भी समय माल वापस कर सकता है, वापसी के बाद अर्जित किराए के किसी भी शेष का भुगतान करने की बाध्यता के बिना; जब तक शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, संपत्ति मालिक के पास ही रहती है। वह साधन जिसके द्वारा किराया-खरीद की जाती है, उसे आमतौर पर बिक्री के बिल के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है (उदाहरण क्रॉकौर (1878) 9 सीएच डी 411 जे); दिवालियापन अधिनियम, 1914 (उदाहरण ब्रूक्स (1883) 23 अध्याय डी 261) के तहत किराये पर लेने वाला 'प्रतिष्ठित मालिक' है; लेकिन किराये पर लेने वाला फैक्टर अधिनियम या माल की बिक्री अधिनियम, 1893 के

तहत 'खरीदने के लिए सहमत' नहीं है, ताकि वह माल को बेचने या गिरवी रखने में सक्षम हो जैसे कि वह एक व्यापारिक एजेंट था (हेल्बी बनाम मैथ्यूज (1895) ए सी 471); ब्रूक्स बनाम बायर्नस्टीन (1909) 1 केबी 98)। ऐसे समझौतों को ली बनाम बटलर (1893) 2 क्यूबी 318 जैसे समझौतों से अलग किया जाना चाहिए, जो वास्तव में एक बिक्री है, किस्तों में कीमत का भुगतान इस शर्त के साथ किया जाता है कि संपत्ति तब हस्तांतरित हो जाती है जब सभी किश्तों का भुगतान कर दिया गया हो; यहां पक्षकार के लिए खरीदारी के लिए एक बाध्यकारी समझौता है, जबकि वास्तविक किराया-खरीद समझौते में ऐसा नहीं है।"

हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, तीसरे संस्करण, खंड 19, अनुच्छेद 823, पृष्ठ 510-511 में, किराया-खरीद लेनदेन की प्रकृति इस प्रकार व्यक्त की गई है:

"किराया खरीद का अनुबंध जमानत के अनुबंध के प्रकारों में से एक है, लेकिन यह वाणिज्यिक जीवन का एक आधुनिक विकास है, और जमानत के संबंध में नियम, जो किराया खरीद के किसी भी अनुबंध पर विचार करने से पहले निर्धारित किए गए थे, को सरलता से लागू नहीं किया जा

सकता है, क्योंकि इस तरह के अनुबंध में न केवल जमानत का तत्व होता है, बल्कि बिक्री का तत्व भी होता है। सामान्य कानून में 'किराया खरीद' शब्द ठीक से केवल खरीद के विकल्प प्रदान करने वाले किराये के अनुबंधों पर लागू होता है, लेकिन इसका उपयोग अक्सर उन अनुबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वास्तव में किस्तों द्वारा संपत्ति खरीदने के समझौते होते हैं, इस शर्त के अधीन कि उनमें संपत्ति जब तक सभी किश्तों का भुगतान नहीं हो जाता, पारित नहीं होगा। हालाँकि, इन दो प्रकार के किराया खरीद अनुबंधों के बीच अंतर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद के प्रकार के अनुबंध के तहत किराएदार पर खरीदने का बाध्यकारी दायित्व होता है और इसलिए किराएदार विश्वास के साथ और वास्तविक मालिक के अधिकारों की सूचना के बिना उसके साथ सौदा करने वाले खरीदार या गिरवीदार को एक अच्छा शीर्षक दे सकता है, जबकि एक अनुबंध के मामले में जो केवल खरीदने का विकल्प प्रदान करता है, किराए पर लेने वाले पर खरीदने के लिए कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं है, और कोई क्रेता या गिरवीदार किराएदार से बेहतर कोई शीर्षक प्राप्त नहीं कर सकता है, सिवाय बाज़ार में बिक्री के मामले को छोड़कर, अनुबंध कारक अधिनियम,

1889, या माल की बिक्री अधिनियम, 1893 के तहत खरीदने का समझौता नहीं है।"

ऊपर उद्धृत टिप्पणियाँ ज्यादातर दो प्रमुख मामलों पर आधारित हैं जिन्हें इस विषय पर लोकस क्लासिक्स के रूप में माना गया है, अर्थात् ली बनाम बटलर ((1893] 2 क्यू.बी. 318) जिसमें लेनदेन को लॉर्ड एशर, एम.आर. द्वारा "किराया और खरीद समझौते" के रूप में वर्णित किया गया था और हेल्बी बनाम मैथ्यूज ([1895] ए.सी. 471) जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पिछले मामले को इस आधार पर अलग किया कि उस मामले में खरीदने के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध था और न कि बिना किसी दायित्व के केवल खरीदने का एक विकल्प। इन दोनों मामलों का निर्णय फेक्टर्स अधिनियम 1889 (52 और 53 विक्ट. सी. 45, धारा 9) के अनुसार किया गया था। उपरोक्त दो प्रमुख मामलों द्वारा उदाहरणित दोनों प्रकार के समझौतों को अब 'किराया-खरीद' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा जैसा कि किराया खरीद अधिनियम, 1938 की धारा 21 (1 और 2 जियो., 6, सी. 53) में निहित है:-

"'किराया-खरीद समझौता' का मतलब माल के उपनिधान के लिए एक समझौता है जिसके तहत जमानतदार सामान खरीद सकता है या जिसके तहत माल में संपत्ति जमानतदार को दे दी जाएगी या दी जा सकती है, और जहां दो या दो

से अधिक समझौतों के आधार पर, जिनमें से कोई भी अपने आप में किराया-खरीद समझौता नहीं बनता है, वहां माल का उपनिधान होता है और या तो जमानतदार माल खरीद सकता है, या उसमें मौजूद संपत्ति जमानतदार को दे दी जाएगी या दी जा सकती है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समझौतों को उस समय किए गए एकल समझौते के रूप में माना जाएगा जब अंतिम समझौता किया गया था।"

यह स्पष्ट है कि कानून के तहत, जैसा कि अब है, जिसे अब ऊपर उद्धृत किराया खरीद अधिनियम की धारा में स्पष्ट कर दिया गया है, लेनदेन बिक्री के तत्व के साथ एक अनुबंध या जमानत की प्रकृति का हिस्सा है, जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, इसमें जोड़ा गया है। ऐसे समझौते में, किराए पर लेने वाला व्यक्ति किराए पर ली गई वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है; वह हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन किसी भी मामले में, यदि खरीदने की बाध्यता है, या खरीदने का विकल्प है, तो मालिक द्वारा माल किराए पर लेने वाले को इन शर्तों पर दिया जाएगा कि किराये पर लेने वाला, प्रीमियम के साथ-साथ कई किस्तों के भुगतान पर, माल के उपयोग का आनंद उठाएगा, जो अंततः उसकी संपत्ति बन सकता है, लेनदेन किराया खरीद के बराबर है, भले ही माल का स्वामित्व उसके पास बना रहे, मालिक और किराएदार को माल का स्वामित्व तब तक पास नहीं करेगा जब तक कि कोई निश्चित घटना न घट जाए, अर्थात्, कि सभी

निर्धारित किस्तों का भुगतान कर दिया गया हो, या कि किराएदार ने नाममात्र या अन्य राशि के भुगतान पर खरीद को अंतिम रूप देने के लिए अपने विकल्प का उपयोग किया हो।

लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सामान खरीदने के लिए कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है और यह स्वामित्व मालिक द्वारा कीमत के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में नहीं बल्कि पूरी तरह से बरकरार रखा जाता है। समझौते की तीसरी शर्त के अनुसार, किराये पर लेने वाले द्वारा समझौते की शर्तों का विधिवत पालन करने और मासिक किस्तों के भुगतान के विशेष संदर्भ में, "किराए पर लेना समाप्त हो जाएगा और वाहन, विकल्प पर किराये पर लेने वाला, उसकी पूर्ण संपत्ति बन जाता है; लेकिन जब तक उपरोक्त भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक वाहन मालिकों की संपत्ति बना रहेगा। किराये पर लेने वाले के पास इस समझौते की अवधि के दौरान यहां पहले उल्लेखित सभी किराये की शेष राशि एकमुश्त किस्त आपूर्ति और लेन-देन से संबंधित मालिकों द्वारा किया गया कोई अन्य खर्च का किसी भी समय भुगतान करके वाहन खरीदने का विकल्प होगा।"

इसलिए, यह स्पष्ट है कि किराए पर लेने के अनुबंध के अलावा किराएदार को खरीदने या न खरीदने का विकल्प भी दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के तर्क में अधिक गंभीर सवाल यह है कि क्या स्पष्टीकरण

में गैर-अप्रत्याशित खंड "इस बात के बावजूद कि विक्रेता कीमत के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में किसी भी सामान का स्वामित्व बरकरार रखता है" स्पष्टीकरण के मुख्य खंड को शासित करता है। हमारी राय में, ऐसा नहीं है। गैर-अप्रत्याशित खंड केवल मुख्य खंड में निहित कानून के स्पष्ट कथन पर जोर देने के लिए जोड़ा गया है, जिसके अनुसार किराया-खरीद आदि पर माल का हस्तांतरण 'बिक्री' माना जाएगा, भले ही ऐसा हो इस आशय की एक शर्त कि माल किराए पर लेने वाले को हस्तांतरित करने के बावजूद, मालिक उन सामानों पर मालिकाना हक तब तक बरकरार रखता है जब तक कि अंतिम घटना नहीं हो जाती, यानी किराएदार के विकल्प पर मालिकाना हक पूरा नहीं हो जाता।

इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचाराधीन समझौते में न केवल उपनिधान सरलीकरण का अनुबंध शामिल है, बल्कि बिक्री का एक तत्व भी शामिल है, जिस तत्व को बिक्री कर जैसे लेनदेन के अधीन करने के उद्देश्य से विधायिका द्वारा मान लिया गया है।

यह हमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क के दूसरे आधार पर ले जाता है, अर्थात्, इस स्पष्टीकरण से, यदि इसका 'बिक्री' की अवधारणा को उस चीज़ तक विस्तारित करने का प्रभाव है जो, कानून में, वास्तविक बिक्री नहीं है, बल्कि केवल एक प्रारंभिक या अपूर्ण विक्रय, तो जहां तक कानून ने 'बिक्री' की परिभाषा का विस्तार किया है, यह असंवैधानिक है।

मिठन लाल के मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, इस तर्क ने अपना महत्व खो दिया है, अगर कभी इसका कोई महत्व था।

लेकिन फिर यह तर्क दिया गया कि मिठन लाल के मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर आगे के तर्कों पर विचार नहीं किया। यह सच है कि मिठन लाल के मामले में यह तर्क नहीं उठाया गया था कि विचाराधीन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। इसलिए, इस न्यायालय के पास विवाद के उस पहलू पर निर्णय देने का कोई अवसर नहीं था, इसलिए, हमें शीर्षक (3) के तहत तर्क पर विचार करना होगा, अर्थात्, यद्यपि संसद के पास ऐसी किसी चीज़ पर कर लगाने की शक्ति हो सकती है जो वास्तव में 'बिक्री' नहीं है, यह कानून इस तर्क के लिए खुला है कि यह दिल्ली में व्यापारियों के खिलाफ भेदभाव करता है, क्योंकि आगे यह भी तर्क दिया गया है कि ऐसा कानून पूरे भारत में लागू नहीं किया गया है। हमारी राय में, इस विवाद में कोई दम नहीं है क्योंकि इस तरह के विवाद का समर्थन करने के लिए दलीलों में कोई उचित आधार नहीं रखा गया था। ऐसा नहीं कहा गया है कि अन्य भाग 'सी' राज्यों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार नहीं किया गया है। दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (LXXIV/1956) के तहत, 'बिक्री' की परिभाषा में ऊपर चर्चा किए गए गैर-विषयक खंड के

बिना, विस्तारित परिभाषा शामिल है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2(जी) की परिभाषा है:

> "अपनी व्याकरणिक विविधताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ 'बिक्री' का अर्थ है नकद या स्थगित भुगतान या किसी अन्य प्रतिफल के बदले एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, और इसमें किराया खरीद या किश्तों द्वारा भुगतान की अन्य प्रणाली पर माल का हस्तांतरण शामिल है, लेकिन इसमें बंधक या बंधक या माल पर कोई शुल्क या गिरवी शामिल नहीं है।"

इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि किराया-खरीद लेनदेन को केंद्रीय बिक्री कर के प्रयोजन के लिए बिक्री की परिभाषा के भीतर शामिल किया गया है', और यह परिभाषा पूरे भारत में लागू हो गई है, और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली राज्य और अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को शत्रुतापूर्ण भेदभाव के लिए चुना गया है। इसलिए, हमारी राय में, इस तर्क में कोई दम नहीं है कि मुख्य क़ानून में 'बिक्री' की विस्तारित परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

अब, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए शेष तर्कों का निस्तारण यह देखते हुए किया जा सकता है कि बिक्री कर विभाग जो करता है, या नहीं करता है, वह कानून को नहीं बदल सकता है। किस्त आपूर्ति लिमिटेड,

नई दिल्ली बनाम दिल्ली राज्य (एआईआर 1956 पंजाब 177) में पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले में निर्धारित कानून के अनुरूप, विभाग ने बिक्री कर अधिकारियों को अपने निर्देश जारी किए। इस न्यायालय ने बाद में मिठन लाल ([1959] एससीआर 445) के मामले में कानून को अधिक आधिकारिक रूप से निर्धारित किया और विभाग इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई बातों पर ध्यान देने के लिए बाध्य था। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि विभाग ने, किसी भी तरह से उन निर्देशों को जारी करके खुद को विबन्धित कर लिया था, या कि इस न्यायालय ने, मिठन लाल के मामले में कानून की स्थिति स्पष्ट करके कानून का एक नया नियम निर्धारित किया था, जो दिल्ली या अन्यत्र बिक्री कर लगाने, मूल्यांकन और वसूली के लिए लंबित कार्यवाही पर लागू नहीं होता है।

किस्त आपूर्ति लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम दिल्ली राज्य में पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए न्यायिक मुद्दे का एक और जवाब है। यह सुस्थापित है कि कराधान के मामलों में पुनर्न्याय का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष का मूल्यांकन केवल उस वर्ष के लिए अंतिम होता है और बाद के वर्षों को नियंत्रित नहीं करता है, क्योंकि यह केवल एक विशेष अवधि के लिए कर निर्धारित करता है। (सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ हेल्थ बनाम होप (मूल्यांकन अधिकारी) ([1960] एसी 551) में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में निर्णय देखें, जिसने ब्रोकन हिल प्रोप्राइटरी कंपनी लिमिटेड बनाम

म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ ब्रोकन हिल में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का अनुपालन किया है)

चूंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए सभी तर्क विफल हो गए, इसलिए यह याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।